



जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वह नियति है, जिस तरह से आप खेलते हैं वह स्वतंत्र इच्छा है।

-जवाहरलाल नेहरू

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube 4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 11 ● अंक: 191 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, सोमवार 18 अगस्त, 2025

उद्घाटन मुकाबले में मेरठ ने... 7 'कल्याण' बिना टीएमसी का होगा... 3 जानबूझकर काटे जा रहे पिछड़ों के... 2

विपक्ष सीईसी के खिलाफ लाएगा महाभियोग!

इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ

संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा

- सरकार व चुनाव आयोग पर विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल
- अभी और बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस
- नेताओं ने कहा- जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद भवन में सोमवार सुबह इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की संभावना पर चर्चा हुई। गठबंधन के नेताओं ने माना कि जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाकर सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि अभी औपचारिक विचार नहीं हुआ है, लेकिन अगर हालात बने तो गठबंधन इस विकल्प को अपनाएगा।

महाभियोग प्रस्ताव लाकर संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। वहीं मानसून सत्र के दौरान लोकसभा व राज्य सभा में भी इस मुद्दे को लेकर सरकार व चुनाव आयोग पर जोरदार हंगामा हुआ। ज्यादा शोरशराबे की वजह से दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। वता दें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के पांच मिनट के भीतर ही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

“ अब पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलीभगत करके चुनाव चुरा रहा है। ”



राहुल गांधी ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप

राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल ने कहा कि अब पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलीभगत करके चुनाव चुरा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा

कि विपक्षी इंडिया गठबंधन उन्हें एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने और हटाने के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनावों को चुराने के उनके षड्यंत्र में सफल नहीं होने देगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वह न तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से डरते हैं और न ही चुनाव आयोग से डरने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कानून में बदलाव करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाई के दायरे से मुक्त किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि वोट चोरी के कारण चुनाव आयोग पर किसी तरह की कार्यवाई हो।



लोकसभा में लगे 'वोट चोर-गद्दी छोड़' के नारे

संसद में सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर नारेबाजी की। सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ और वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर की चेतावनी के बावजूद हंगामा जारी रहा। इसके चलते लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी नारेबाजी जारी रही। इस कारण सदन दोबारा 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेंबर में विपक्ष की बैठक

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेंबर में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। इसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। दरअसल, एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार ने कहा था- राहुल गांधी की तरफ से पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से भागी जाओ। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा।

चिराग ने राहुल पर बोला हमला

यह बात समझ से बाहर है कि इस यात्रा से उनका क्या लाभ होगा और प्रदेश को क्या फायदा होगा। यह बात चुनाव आयोग भी कह रहा है और हम लोग भी तय कर रहे हैं कि हर नागरिक को वोट दे का अधिकार मिले और देश का जो नागरिक नहीं है मुक्त है उसका नाम तो कटना ही चाहिए। यही मांग विपक्ष की भी थी। लोजपा समितिलास के नेता ने कहा कि आप अगर किसी भी संवैधानिक संस्था का विश्वास ही नहीं कीजिएगा तो देश अराजकता में तो नहीं जा सकता वह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।

विपक्ष पर मड़के लोकसभा अध्यक्ष



बिहार में मतदाता सूची संशोधन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर विपक्ष को कड़ी कार्यवाई की चेतावनी दी और कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया।

आयोग भी हलफनामा दे : अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा द्वारा दिये गये शपथपत्र प्राप्त नहीं होने का दावा करने वाला आयोग उन हलफनामों की प्राप्ति की पावती पर गौर करे। अखिलेश यादव ने एक्स पर कहा, जो निर्वाचन आयोग यह कह रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए हलफनामे नहीं मिले हैं, वह हमारे शपथपत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गयी अपने कार्यालय की पावती को देख ले। उन्होंने कथित रूप से डाक विभाग द्वारा दी गयी रसीदों की तस्वीरें भी टैग करते हुए लिखा, इस

बार हम मांग करते हैं कि निर्वाचन आयोग शपथपत्र दे कि यह जो डिजिटल रसीद हमें भेजी गयी है वह सही है, नहीं तो निर्वाचन आयोग के साथ-साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी जाए तो सत्यता आए। अखिलेश यादव का यह बयान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा एक प्रेसवार्ता में 'वोट चोरी' और अन्य अनियमितताओं के विपक्ष के आरोपों को गलत बताए जाने के बाद आया है। अखिलेश यादव ने इससे पहले 'एक्स' पर एक अन्य संदेश में कहा था कि सपा ने 'वोट डकैती' के 18 हजार शपथ पत्र आयोग को दिए थे लेकिन कार्यवाई शून्य है।



जानबूझकर काटे जा रहे पिछड़ों के वोट: अखिलेश

» सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर किया हमला

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अगर चुनाव आयोग हमें वोटर लिस्ट उस फॉर्म में दे दे जिस फॉर्म में हमें चाहिए तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जानबूझकर पिछड़ों का वोट काटते हैं और दिखाते ये हैं कि पिछड़ा वोट उन्हें (बीजेपी) मिल रहा है। लेकिन, सच्चाई ये है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। शाहगंज, छिबरागंज में हम कितने कम वोट से हारे हैं। अगर ये हमें सही वोटर लिस्ट दे दें तो सारी चीजे साफ हो जाएंगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है तब से एक भी शिकायत पर अधिकारी को नहीं हटाया गया।

इसका मतलब है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बात मानता है। हमारा कहना है कि अगर एक ऐसे डीएम पर कार्रवाई हो जाए तो किसी को वोट नहीं कटेगा। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस विधानसभा



जाति के आधार पर प्रेसाइडिंग अफसर व बीएलओ तैनात होते हैं

अखिलेश यादव ने कहा कि अनुराग तिवारी ने भी कन्नौज को लेकर आरोप लगाए थे, हमारी पार्टी ने बहुत सारे फर्जी वोटों को डिलीट कराया है, हमारी मांग केवल इतनी है कि जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रेसाइडिंग अफसर मत बनाइए, आप तय कर लें कि किस अधिकारी को वोट डिलीट करना है। आप यूपी के आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो वो किस अधिकारी या एडीएम के अंडर में होगा, अगर एक भी अधिकारी पीडीए का हुआ तो बता देना।

बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने उनके वोट डिलीट करा दिए। हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो बीजेपी के वोट हैं।

आरोपी अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?

बीजेपी ने कोई एसडीएम, एसओ और सीओ की शिकायत की होगी उसे हटाया गया।

में हराया गया था, वहां इलेक्शन कमीशन सीधा एसओ और पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था। ऐसे में सबसे जरूरी सवाल ये

है कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। हम विपक्ष के लोग हैं जो हमें अच्छा नहीं लगेगा हम विरोध करेंगे।

भाजपा विपक्ष को दुश्मन मानती है

अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सरकार में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी भेदभाव का शिकार हैं। भाजपा विपक्ष को दुश्मन मानती है। भाजपा सरकार में बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। सड़कों में गड्ढे हैं। निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। भाजपा सरकार 9 साल के कार्यकाल में सड़कों के गड्ढे भी नहीं भर पाई। इस सरकार में बने एक्सप्रेसवे में भी बड़े-बड़े गड्ढे हैं। समाजवादी पार्टी, भाजपा को सत्ता से हटाएगी।

वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं को जागरूक करेगी सपा

सपा वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं को जागरूक करेगी। इतना ही नहीं मतदाता सूची में गड़बड़ के खिलाफ गांव-गांव अभियान भी चलाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सपा एक ओर चुनाव आयोग से अंतरात्मा की आवाज सुनकर निष्पक्ष रहने की अपील कर रही है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग के गड़बड़ियों पर ध्यान न देने के खिलाफ जन अभियान भी चला रही है।

स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सुप्रीमो पर साधा निशाना

यूपी सरकार में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सोशल मीडिया वाले नेता लगातार हार से हताश हैं। कुर्सी खो चुके सपनों के सौदागर जनता को गुमराह करने के लिए चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अखिलेश यादव के दागदार शासन को अभी तक लोग भूले नहीं हैं। जलशक्ति मंत्री ने चुनाव आयोग पर अखिलेश के आरोपों के जवाब पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव लोकतंत्र के मसीहा नहीं, सपा के गुंडराज के वारिस हैं। उन्हें लोकतंत्र की नहीं, कुर्सी की चिंता है। अब आयोग पर उंगली उठाकर अपनी डूबती नैया बचाना चाहते हैं।

असीम अरुण पर अखिलेश यादव का पलटवार

समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज में मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा नई बहस छेड़ दी है। अब सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने उनके बयान पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ ऐसा नहीं बचा था, जहां पर भाजपा समर्थकों के गलत तरीके से वोट न काटे गए हों। यह चुनाव प्रक्रिया में निश्चित रूप से गड़बड़ी है। कन्नौज में इसका लाम अखिलेश यादव ने लिया। वहां गलत ढंग से वोट कुंजे हुए थे। इस पर अखिलेश यादव ने एक्स के माध्यम से सवाल उठाया कि क्या भाजपा के इन विधायक और मंत्री का एंफिडेविट चुनाव आयोग पहुंच गया। चुनाव आयोग इनके खिलाफ क्या करेगा, इसका शपथपत्र न सही तो श्वेतपत्र दे।

कांग्रेस के पास पहले उदार हृदय वाला नेतृत्व था: पवार

» महाराष्ट्र के पूर्व सीएम बोले- वसंतदादा सरकार गिराई, फिर भी 10 साल बाद सीएम पद के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पुणे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने 1978 में वसंतदादा पाटिल के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को गिराने की पहल की थी। इसके बावजूद उन्होंने एक दशक बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया।

शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि उस समय कांग्रेस के पास इस तरह का उदार हृदय वाला नेतृत्व था। शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) बनाई। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार के तत्कालीन शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी दोफाड़ हो गई। 84 साल के राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे।



उन्होंने याद किया कि आपातकाल के बाद यह भव्य पुरानी पार्टी कांग्रेस (इंदिरा) और स्वर्ण सिंह कांग्रेस में विभाजित हो गई। उस समय वह अपने गुरु यशवंतराव चव्हाण के साथ स्वर्ण सिंह कांग्रेस में ही रहे, लेकिन बाद में हुए चुनावों में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, आखिरकार हम एकजुट हुए और वसंतदादा को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि, हममें से कई युवा कार्यकर्ताओं में कांग्रेस (आई) के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि हम चव्हाण साहब के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए एक दूरी थी। दादा ने इसे पाटने की कोशिश की, लेकिन हमने इसका विरोध किया। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैं प्रमुख विरोधियों में से एक था। इस वजह से हमने सरकार गिराने का फैसला किया और हमने ऐसा किया।

सरकार की छवि बिगाड़ने की साजिश हो रही: शिवकुमार

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु। कर्नाटक के धर्मस्थल करबे में विभिन्न जगहों पर शवों को सामूहिक रूप से दफनाए जाने के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंदिर सूचना केंद्र और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया।

इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने धर्मस्थल में शवों को सामूहिक रूप से दफनाए जाने के आरोपों को इलाके की छवि बिगाड़ने की साजिश करार दिया। एसआईटी ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ धर्मस्थल मंदिर परिसर पहुंचे अधिकारियों ने एक सार्वजनिक शौचालय के पास महाजर (मौके पर निरीक्षण) किया और उस जगह का भी निरीक्षण किया, जहां शिकायतकर्ता पिछले



वर्षों में मंदिर में काम करते हुए कथित तौर पर रुका था। यह निरीक्षण कड़ी पुलिस सुरक्षा में हुआ। अधिकारियों ने कहा कि निरीक्षण नियमित जांच प्रक्रिया का हिस्सा था और निष्कर्षों के आधार पर चिन्हित स्थानों की आगे

फॉरेंसिक जांच की जा सकती है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से कहा, सैकड़ों वर्षों की विरासत को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। किसी को यूं ही बदनाम करना सही नहीं है। यह सब एक शिकायतकर्ता की वजह से हुआ है। शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने धर्मस्थल को बदनाम करने के अभियान में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, मैंने उनसे (कांग्रेस विधायकों से) कहा है कि छवि खराब करने के अभियान में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

वोटर लिस्ट देने में एतराज क्यों: दिग्विजय सिंह

» पूर्व मुख्यमंत्री बोले- बिहार में 65 लाख वोट डिलीट हुए

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

इंदौर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है?

हमने वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी मांगी है, ताकि हम उसके माध्यम से यह जानकारी ले सकें कि व्यक्तियों के नाम एक पोलिंग बूथ पर है या दूसरे पोलिंग बूथों पर है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को खुलकर आरोपों पर जवाब देना चाहिए। बिहार में 65 लाख वोटों के नाम हटाए गए। वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी देने में क्या एतराज है। वो हमें क्यों नहीं दी

जा रही है। सिंह ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दो सप्ताह तक वोट अधिकार यात्रा आरजेडी, कांग्रेस व साथी दल बिहार में निकालेंगे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश में माहौल खड़ा किया था। हम भी देश को जागृत कर रहे हैं। सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल द्वारा लिखी गई किताब का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे भी शामिल हुए, लेकिन वे दिग्विजय सिंह से दूर-दूर नजर आए। सिंह के साथ पूर्व नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा थे, लेकिन चौकसे दूसरी पंक्ति में बैठे।



R3M EVENTS

ACTIVATION · EVENTS · EXHIBITION

R3M EVENTS

4/725 Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail: rajendra@r3mevents.com, Mob : 095406 11100

'कल्याण' बिना टीएमसी का होगा 'कल्याण' विस चुनाव से पहले तृणमूल बना रही रणनीति

- » कल्याण को अहम पद से हटाकर दीदी ने दिया कड़ा संदेश
- » सीएम ने बढ़ाया अभिषेक बनर्जी का कद
- » भाजपा ने भी संभाला मोर्चा
- » कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक पद से हटाने पर सवाल

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। वहां पर सियासी बखेड़ा अभी से शुरू हो गया है। सत्ता बैठी टीएमसी एकबार फिर राज्य में सरकार बनाने की जुगत में लगी है तो भाजपा उसे उतारकर बंगाल में हिंदुत्व का पताका फहराना चाहती है। भाजपा के सारे दिग्गज नेता समय-समय पर ममता सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाकर हमलावर रहते हैं।

वहीं टीएमसी भाजपा पर सांप्रदायिकरण फैलाने का हवाला देकर उसको घेरती रहती है। इन सबके बीच सीएम ममता बनर्जी व पार्टी की मुखिया ममता अपने सांसदों की चूड़ी कसने में भी पीछे नहीं रहती हैं। जहां तक तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी के लगातार बढ़ते ग्राफ की बात है तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पहले से ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अब संसद में भी उन्हें नेतृत्व सौंपने से संकेत साफ है कि टीएमसी नेतृत्व का उत्तराधिकार धीरे-धीरे उनके हाथों में केंद्रित हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपने वरिष्ठ नेता और बांकुड़ा से सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी के मुख्य सचेतक पद से हटा दिया है साथ ही लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता पद से सुदीप बंधोपाध्याय को हटा कर अभिषेक बनर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उल्लेखनीय है कि सुदीप बंधोपाध्याय लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे हैं इसलिए उनकी जगह तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को लाया गया है। लेकिन कल्याण बनर्जी को अपना पद जिन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा है उसे महज संगठनात्मक फेरबदल नहीं माना जा सकता। दरअसल, यह बदलाव तृणमूल के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन, आंतरिक खींचतान और आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की रणनीति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है।



कल्याण बनर्जी ने लगाए आरोप

उधर, लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने वाले कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सांसदों के बीच समन्वय की कमी के लिए उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि कुछ सांसद संसद में बमुश्किल ही आते हैं। कल्याण बनर्जी ने यह कदम पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की अध्यक्षता में तृणमूल सांसदों की डिजिटल तरीके से आयोजित एक बैठक के कुछ घंटे बाद उठाया। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी के संसदीय दल में खराब समन्वय पर अप्रसन्नता

जतायी थी। कल्याण बनर्जी ने एक चैनल से कहा, "मैंने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया है, क्योंकि 'दीदी' (पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) ने डिजिटल बैठक के दौरान कहा था कि पार्टी सांसदों के बीच समन्वय की कमी है। इसलिए दोष मुझ पर है। इसलिए, मैंने पद छोड़ने का फैसला किया है।" भावुक होते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि वह एक साथी सांसद द्वारा उनके अपमान पर पार्टी की चुप्पी से बहुत आहत हैं। उनका इशारा परोक्ष तौर पर महुआ मोइत्रा की ओर था। नब्बे के दशक के उत्तरार्ध से तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के साथ रहे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने कहा, दीदी कहती हैं कि लोकसभा सदस्य लड़ रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं... क्या मुझे उन लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए जो मुझे अपशब्द कहते हैं? मैंने पार्टी को सूचित किया, लेकिन मेरा अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, वे मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से चाहें पार्टी को चलायें।" उन्होंने पार्टी के आंतरिक मामलों पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैं इतना क्षुब्ध हूँ कि मैं राजनीति छोड़ने के बारे में भी सोच रहा हूँ।"

स्वेच्छा से इस्तीफा देने का दावा

हम आपको यह भी बता दें कि एक ओर कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, खासकर कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ महीनों तक चले तनाव और उससे पहले पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद के साथ तनाव के बीच। कल्याण बनर्जी ने अपने इस्तीफे से ठीक पहले

'एक्स' पर एक लंबी पोस्ट में महुआ मोइत्रा पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने पोस्ट में कहा था, "मैंने महुआ मोइत्रा द्वारा हाल ही में एक सार्वजनिक पॉडकास्ट में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। उनके शब्दों का चयन, जिसमें एक साथी सांसद की तुलना सुअर से करने जैसी अमानवीय भाषा का प्रयोग शामिल है, न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सभ्य संवाद के बुनियादी मानदंडों की उपेक्षा को भी दर्शाता

है।" उन्होंने लिखा, "किसी पुरुष सहकर्मी को %यौन रूप से कुटित कहना कोई साहस नहीं है- यह सरासर दुर्व्यवहार है। अगर ऐसी भाषा किसी महिला के लिए इस्तेमाल की जाती, तो पूरे देश में आक्रोश फैल जाता और यह सही भी है। लेकिन जब कोई पुरुष निशाना होता है, तो इसे या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर सराहा जाता है। एक बात साफ है- दुर्व्यवहार तो दुर्व्यवहार ही होता है- चाहे वह किसी के साथ हो।"

तृणमूल की रणनीतिक चुस्ती और नेतृत्व सशक्तीकरण को बढ़ाना

इसके अलावा, अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल की कमान सौंपना एक ओर तृणमूल की रणनीतिक चुस्ती और नेतृत्व

सशक्तीकरण को दर्शाता है, तो दूसरी ओर यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक संवाद की जगह

केंद्रीकरण ने ले ली है? देखा जाये तो यह बदलाव एक दोधारी तलवार की तरह है- जो पार्टी को अनुशासित भी कर सकता है

और आंतरिक असंतोष को हवा भी दे सकता है। आगामी महीनों में इस बदलाव का असली असर तब दिखेगा जब टीएमसी

लोकसभा में अपनी रणनीति को नया आकार देगी और विपक्षी दलों के साथ अपने रिश्ते फिर से परिभाषित करेगी।

मोइत्रा पर बरसे कल्याण बनर्जी

कल्याण बनर्जी ने कहा था, "अगर मोइत्रा सोचती है कि अपशब्द कहने से उनकी अपनी नाकामियां छिप जाएंगी या उनके रिकॉर्ड पर गंभीर सवालों से ध्यान हट जाएगा, तो वह खुद को धोखा दे रही है। जो लोग जवाब देने के बजाय अपशब्दों पर गंभीर करते हैं, वे लोकतंत्र के चैंपियन नहीं हैं- वे इसकी शर्मिंदगी हैं और इस देश के लोग उनकी इस हरकत को समझ सकते हैं।" हम आपको बता दें कि श्रीरामपुर से चार बार के सांसद कल्याण बनर्जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं कि अनुशासनहीनता और कम उपस्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की बजाय पार्टी उन्हें ही दोषी ठहरा रही है। कल्याण बनर्जी ने कहा, "ममता बनर्जी ने जिन्हें सांसद

बनाया है, वे लोकसभा आते भी नहीं हैं। दक्षिण कोलकाता, बैरकपुर, बांकुड़ा, उत्तर कोलकाता के तृणमूल सांसदों में से शायद ही कोई संसद आता है। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या कसूर है? मुझे ही हर चीज के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने साथ ही एक बांग्ला टीवी चैनल से कहा, अगर ज्यादातर सांसद संसद से नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, तो मैं क्या करूँगा? क्या ममता बनर्जी जानती हैं कि संसद का दैनिक कामकाज कैसे चल रहा है? अगर पार्टी कदम नहीं उठाए, तो मैं क्या करता? मैंने सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का स्कॉलर नहीं हूँ। मैं मंहंगी साइडिंग नहीं पहनता। जो लोग ममता बनर्जी की आलोचना करते हैं, उन्हें इनाम मिलता है।



अभिषेक पर बढ़ रही जिम्मेदारी

जहां तक तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी के लगातार बढ़ते ग्राफ की बात है तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे पहले से ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अब संसद में भी उन्हें नेतृत्व सौंपने से संकेत साफ है कि टीएमसी नेतृत्व का उत्तराधिकार धीरे-धीरे उनके हाथों में केंद्रित हो रहा है। संसदीय दल का नेता बनाना केवल प्रतीकात्मक पद नहीं है, यह निर्णय केंद्रीय राजनीति में पार्टी की आवाज किसके माध्यम से पहुंचेगी, इसका स्पष्ट संकेत है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों में देश का पक्ष रखने के लिए भेजा था तब सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसद युसूफ पटान का नाम तय किया था लेकिन ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताते हुए उनकी जगह अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल करवाया था और संदेश दिया था कि देश के स्तर पर हो या दुनिया के स्तर पर, तृणमूल का भावी चेहरा अभिषेक बनर्जी ही होंगे।

सांसदों के बीच गुटबाजी अस्वीकार्य: ममता बनर्जी

बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने बैठक में किसी का नाम लिये बिना स्पष्ट किया कि सांसदों के बीच गुटबाजी अस्वीकार्य है और कहा कि पार्टी को संसद में एकता प्रदर्शित करनी चाहिए। इस बीच, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि ममता बनर्जी विशेष रूप से लोकसभा में एकजुटता की कमी से परेशान थीं। तृणमूल के एक नेता के अनुसार ममता बनर्जी ने बैठक में कहा, "राज्यसभा का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन लोकसभा सांसदों का

प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय अस्वस्थ हैं और सौगत रॉय भी। वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में समन्वय चरमरा गया है। हम आपको बता दें कि कल्याण बनर्जी पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह अभिषेक बनर्जी की नई पीढ़ी की नेतृत्व शैली से असहज दिखते रहे हैं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण महुआ मोइत्रा प्रकरण है, जहां कल्याण बनर्जी और मोइत्रा के बीच तीखा सार्वजनिक

विवाद देखने को मिला था। उस समय अभिषेक ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में संकेत दिया था, जिससे कल्याण बनर्जी की स्थिति कमजोर हुई। इस विवाद के बाद से ही अटकलें तेज थीं कि पार्टी में शक्ति संतुलन बदल रहा है। देखा जाये तो टीएमसी के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती



संगठनात्मक अनुशासन और राजनीतिक संदेश की स्पष्टता है। ममता बनर्जी को यह बखूबी समझ आ गया है कि अगर पार्टी को राष्ट्रीय मंच पर गंभीरता से लिया जाना है, तो अंदरूनी विरोध और टकराव की छवि खत्म करनी होगी। कल्याण बनर्जी को हटाने का संदेश साफ है- पार्टी लाइन से अलग चलने वालों को अब कोई छूट नहीं मिलेगी। बहरहाल, ममता बनर्जी का यह निर्णय निश्चित ही बंगाल की राजनीति को कई स्तरों पर प्रभावित करेगा। जैसे-

तृणमूल कांग्रेस के अंदर पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी का संघर्ष और खुलकर सामने आ सकता है। कुछ वरिष्ठ नेता इस निर्णय को निजीकरण या एक परिवार तक सत्ता सिमटने के रूप में देख सकते हैं। विपक्षी दल विशेषकर भाजपा को यह कहने का मौका मिलेगा कि वे इसे 'एक परिवार की पार्टी' करार दें, जिससे ममता बनर्जी के उस नैरेटिव को धक्का लग सकता है जिसमें वह भाजपा को केंद्रीकरण और अधिनायकवाद का प्रतीक बताती रही है।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

मिलावटखोरों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी

हाल ही में कुछ राज्यों में खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें आईं। मिलावट मिठाईयों का कारोबार तो त्योहारों में बहुत तेजी से होता है। पर इधर आम दिनों में मिलावट का धंधा जोरों पर है। ये इतने खतरनाक स्तर का है कि इसकी वजह से लोगों की जान तक चली जा रही है। हालांकि शासन व प्रशासन चाहे तो इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है? मिलावटखोरी वर्तमान समय में सबसे चिंताजनक समस्या है। उत्पादक एवं विक्रेता दोनों ही ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मिलावटखोर तो जो कर रहे हैं वो निंदनीय है ही। अब इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं कि ऑन लाइन खाना मंगाने वालों को झेलना पड़ता है। कभी-कभी उनकी तरफ से समय-समय पर ऐसे वीडियो वायरल किए जाते हैं जिसमें खाने में कभी छिपकली तो कभी अन्य जीव निकलते हैं। सबसे दिलचस्प मामला अभी तेलंगाना में जब एक महिला से कचौड़ी मंगाया उसमें सांप निकला जब इसकी शिकायत दुकानदार से किया गया तो इस मामले को उसे हल्के में लिया बाद में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत। अब सवाल यह उठता है कि खाद्य की जांच करने की एजेंसियां इतनी लापरवाह क्यों हो रही हैं। किसी तीज त्यौहार के समय मिलावट का खेल और भी बढ़ जाता है।

मिलावटखोरी को रोकने के लिए प्रत्येक सक्षम स्तर यानी ग्राम पंचायत से लेकर बड़े शहरों में वार्ड स्तर पर गहन परीक्षण व्यवस्था होनी चाहिए तथा जांच की समयबद्धता एवं कठोर दंड व्यवस्था से ही इस काले कारनामे पर अंकुश लगाया जा सकता है। जांच के बाद यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हो जाती है तो मिलावट करने वाले या मिलावट की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिलावट के खिलाफ लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता अभियान त्यौहारों पर ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी चलाए जाने चाहिए। सख्त कार्रवाई से ही अंकुश लगेगा। खाद्य मिलावट को रोकने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता है। जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय किसानों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। मिलावट रहित भोजन के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाना अनिवार्य है, जिसमें सरकारी एजेंसियां नियमित व अचानक जांच करें और दोषियों पर त्वरित व कठोर कार्रवाई हो। भारी जुर्माने, कारावास और लाइसेंस रद्द करने जैसे दंड से मिलावटखोरों में भय पैदा होगा। उपभोक्ताओं को मिलावट पहचानने के सरल तरीके और शिकायत प्लेटफॉर्म की जानकारी देकर उनकी भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। साथ ही खाद्य सप्लाय चेन में डिजिटल ट्रैकिंग, क्यूआर कोड और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन से उपभोक्ता तक हर चरण पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। इसमें सरकारी अमले व आमजन दोनों को तैयारी करके इसके खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

बायोमेट्रिक वोटर कार्ड में विवादों का हल

पुष्परंजन

पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया, मैं घूमने नहीं, बच्चियों का जबरन खतना किये जाने पर रिपोर्टिंग के लिए गया था। गाम्बिया मैनलैंड अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। इसकी उत्तरी, पूर्वी, और दक्षिणी सीमा सेनेगल से मिलती है। लगभग 28 लाख की आबादी वाले इस देश की एक-तिहाई जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा 1.25 डॉलर प्रतिदिन से नीचे रहती है। दिलो-दिमाग में बैठा हुआ था, कि यह अफ्रीकी देश काफी पिछड़ा हुआ होगा। लेकिन यह भ्रम वहां की पत्रकार फातो कमारा से मिलने के बाद टूट गया। उन्हीं से जानकारी मिली कि गाम्बिया दुनिया का पहला देश है, जहां मतदाताओं के लिए बायोमेट्रिक कार्ड 2009 में इश्यू किया गया था। सितम्बर, 2010 में भारत ने आधार कार्ड जारी किया था, जिसे वोटर कार्ड से भी पहचान के वास्ते जोड़ा जाने लगा। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। चुनाव आयोग ने नागरिकों के लिए अपने आधार नंबर को अपने मतदाता पहचान पत्र (जिसे चुनावी फोटो पहचान पत्र या ईपीआईसी भी कहा जाता है) से जोड़ना स्वैच्छिक बना दिया है।

मतदाताओं को अपने कार्ड लिंक करते समय आधार प्रमाणीकरण के लिए अपनी सहमति फॉर्म 6-बी में देना आवश्यक है। एक बार सहमति दे देने के बाद उसे वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, कि आधार कार्ड होना नागरिकता का प्रमाणीकरण नहीं है। पूरा देश जिस तरह नागरिकता को लेकर बहस में उलझा है, वह भारत में वोटर पहचानपत्र की वैधता पर सवाल खड़ा करता है। क्या भारत में जारी वोटर आई कार्ड दोषपूर्ण है? और यदि है, तो उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? कई देश नागरिकता, या उससे संबंधित पहचान के उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड का उपयोग करते हैं। अल्बानिया, ब्राजील, नीदरलैंड और सऊदी अरब

ऐसे मुल्क हैं, जिनके राष्ट्रीय बायोमेट्रिक पहचान पत्र यात्रा दस्तावेजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के मानक का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं।

इसके अतिरिक्त, नॉर्वे, आइसलैंड और लिश्टेन्टाइन जैसे देश, यूरोपीय संघ के मानकों का पालन करने वाले बायोमेट्रिक पहचान पत्र जारी करते हैं। कुछ देश अपनी व्यापक राष्ट्रीय पहचान प्रणालियों में बायोमेट्रिक्स का उपयोग करते हैं, जिन्हें नागरिकता या उनकी रिहाइश से जोड़ा जा सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश बायोमेट्रिक पहचान



पत्र जारी करने के लिए बाध्य हैं, और इन्हें आमतौर पर ईयू और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के भीतर वैध यात्रा दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) के सदस्य देशों, जिनमें नॉर्वे, आइसलैंड और ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड के बीच छोटा सा देश लिश्टेन्टाइन शामिल हैं, उन्हें भी यूरोपीय संघ के नियमों के अनुरूप बायोमेट्रिक पहचान पत्र जारी करना आवश्यक है। कई देशों ने अनिवार्य राष्ट्रीय पहचान प्रणालियां लागू की हैं, जिनमें अक्सर विभिन्न पहचान उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक डेटा, जैसे उंगलियों के निशान या चेहरे की पहचान, शामिल होता है। इनमें अर्जेंटीना, बेलजियम, कोलंबिया, जर्मनी, इटली, पेरू और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। अल्बानिया, ब्राजील, नीदरलैंड, सऊदी अरब के राष्ट्रीय बायोमेट्रिक पहचान पत्र, यात्रा दस्तावेज माने जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश

गाम्बिया ने बायोमेट्रिक पहचान पत्र, 'गैम्बीस' लागू किए हैं, जो यात्रा के साथ निवास परमिट भी है। तंजानिया भी, गाम्बिया की तरह चुनावों के लिए बायोमेट्रिक मतदाता पंजीकरण को फुलप्रूफ मानता है। पोलैंड अपनी राष्ट्रीय पहचान प्रणाली में फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स का उपयोग करता है। भारत केवल आधार प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक्स का उपयोग करता है, जो बैंकों, कोर्ट और विभिन्न उपक्रमों में केवाईसी या रजिस्ट्रेशन के काम आते हैं। राष्ट्रमंडल पर्यवेक्षक समूह ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय पहचान पत्र

(एनआईडी) जैसी फोटो पहचान प्रक्रिया का उपयोग मतदाता सूची की सटीकता में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है और चुनाव में आम विश्वास बढ़ा सकता है। पिछले एक दशक में, बायोमेट्रिक मतदाता पंजीकरण (बीवीआर) जैसी तकनीक जटिल चुनावी चुनौतियों और जालसाजी का सामना करने के लिए रामबाण साबित हुई है।

'बीवीआर' मतदाता की विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं का विश्लेषण करता है, ताकि उनकी पहचान और मतदान के लिए उनकी पात्रता की पुष्टि की जा सके। यह तकनीक किसी व्यक्ति की पहचान की चोरी, एक से अधिक मतदान, धोखाधड़ी, और हेरफेर के अन्य तरीकों को टारगेट करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आंखों की बायोमेट्रिक। आंखों की रेटिना में हेराफेरी अब तक किसी तकनीक के जरिये सम्भव नहीं हुआ है।

के.एस. तोमर

आठ अगस्त, 2024 को, जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया, तब देश की बिखरी हुई संस्थाओं और हिंसक सड़कों के बीच यह एक ऐतिहासिक प्रयोग था। सेना और नागरिक समाज दोनों ने उम्मीद जताई कि उनकी नैतिक छवि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा राजनीति के दलदल से देश को बाहर निकाल पाएंगी। लेकिन एक साल बाद, तस्वीर उम्मीद से कहीं अधिक धुंधली और तनावपूर्ण हो गई है। आज बांग्लादेश आर्थिक दबाव, युवाओं के गुस्से, राजनीतिक अविश्वास, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और पड़ोसी भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच खड़ा है। यूनुस ने कुछ सुधारों की शुरुआत की, लेकिन आईएमएफ-समर्थित कठोर नीतियों और धीमी राजनीतिक संवाद प्रक्रिया ने हालात को स्थिर होने के बजाय और जटिल बना दिया है।

यूनुस सरकार का सबसे बड़ा दांव आईएमएफ पैकेज रहा, जिसने मुद्रा को स्थिर करने में मदद की। लेकिन इसकी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है-सब्सिडी में कटौती, ईंधन और खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि, और रोजगार के अवसरों में ठहराव के रूप में। तैयार-पोशाक निर्यात क्षेत्र, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव और घरेलू श्रमिक अशांति से जूझ रहा है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यूनुस ने राजकोषीय अनुशासन लागू करने में तो सख्ती दिखाई, लेकिन रोजगार सृजन और छोटे उद्योगों के

प्रतिशोध की राजनीति और चुनावी अस्थिरता

पुनर्जीवन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह है कि महंगाई कम होने के बावजूद जनता को राहत का अहसास नहीं हो रहा। ग्रामीण इलाकों में कृषि लागत बढ़ गई है और शहरी क्षेत्रों में रोजगार संकट गहराता जा रहा है, जिससे आर्थिक असंतोष और बढ़ गया है। शुरुआत में, यूनुस का सबसे बड़ा सामाजिक पूंजी बैंक युवा वर्ग था, जिसने बदलाव की उम्मीद में उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया था।

लेकिन एक साल बाद, बेरोजगारी और अवसरों की कमी के कारण वही युवा सड़क पर हैं। विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर ढाका की सड़कों तक, छात्र संगठनों ने सरकार की नीतियों पर खुलकर नाराजगी जताई है। कई विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और अस्थिर हो गया है। युवाओं की यह अधीरता अगर चुनावी वर्ष में हिंसा में बदल गई तो न केवल यूनुस की साख, बल्कि पूरे संक्रमणकालीन लोकतांत्रिक प्रयोग को भी गंभीर खतरा हो सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि युवाओं का यह गुस्सा सोशल



मीडिया के माध्यम से तेजी से फैल रहा है और इसकी क्षमता है कि वह 2026 के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। भारत ने चुनावी उथल-पुथल के बाद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देकर एक मानवीय और रणनीतिक फैसला लिया, लेकिन इसका असर बांग्लादेश की घरेलू राजनीति पर उल्टा पड़ा। आम बांग्लादेशी, जो हसीना को एक सत्तावादी और अलोकप्रिय नेता मानते हैं, इस कदम को स्वीकार नहीं कर सके।

यूनुस ने सार्वजनिक रूप से भारत के इस निर्णय की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उनके हालिया कदम-चीन के साथ नजदीकी, निवेश परियोजनाओं पर नई वार्ता और बीजिंग समर्थित ढांचागत योजनाओं को प्राथमिकता-ने संकेत दिया है कि वे एक नई कूटनीतिक धुरी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस रणनीति ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में ठंडापन बढ़ा दिया है। नई दिल्ली सतर्क है, जबकि ढाका में यह धारणा बनने लगी है कि यूनुस भारत से दूरी बनाए रखते हुए चीन के पाले में अधिक

सहज हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के परदे के पीछे अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन ने लंबे समय से शेख हसीना के शासन से असंतोष जताया था और सत्ता से उनके हटने की प्रक्रिया को परोक्ष रूप से समर्थन दिया। अमेरिकी रणनीति का मुख्य लक्ष्य बांग्लादेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करना और चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करना था। लेकिन भारत द्वारा हसीना को शरण देने के फैसले ने इस समीकरण में अप्रत्याशित मोड़ ला दिया।

वाशिंगटन, जिसने यूनुस के उदय को चुपचाप समर्थन दिया था, इस कदम से संतुष्ट नहीं है। अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि यह कदम बांग्लादेश के संक्रमणकाल को अनावश्यक रूप से जटिल बना सकता है और यूनुस सरकार पर घरेलू स्तर पर अधिक दबाव डाल सकता है। इस असहमति ने भारत-अमेरिका संवाद में हल्की खटास पैदा कर दी है। हालांकि, सार्वजनिक बयानों में दोनों देश इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में यह स्पष्ट है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली इस बात पर एकमत नहीं हैं कि हसीना को शरण देना दीर्घकालीन दृष्टि से सही था या नहीं। अवामी लीग और बीएनपी के बीच प्रतिशोध की राजनीति इतनी गहरी है कि यूनुस के संवाद मंच भी इसे तोड़ नहीं पाए। अवामी लीग खुद को हाशिये पर महसूस कर रही है, जबकि बीएनपी को आशंका है कि चुनावी सुधार अधूरे रह जाएंगे। चुनाव आयोग का आंशिक पुनर्गठन हुआ है, लेकिन मतदाता सूचियों की सफाई और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में सुस्ती ने विपक्ष को और शंकालु बना दिया है।

एसिडिटी

इन चार आसान तरीकों से मिलेगा छुटकारा

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित दिनचर्या ने हमारे स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डाले हैं, जिनमें से एक आम समस्या है सुबह उठते ही पेट में जलन या एसिडिटी खेना। यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी नहीं, बल्कि दिन की शुरुआत को पूरी तरह खराब कर सकती है और हमें असहज महसूस करा सकती है। रात भर के आराम के बाद जब पेट में तेज जलन, खट्टी डकारें या भारीपन महसूस हो, तो समझना चाहिए कि यह अनियमित खानपान, बढ़ता तनाव और गलत जीवनशैली का सीधा परिणाम है। यह समस्या न केवल शारीरिक बेचैनी पैदा करती है, बल्कि हमारी कार्यक्षमता और मूड पर भी बुरा असर डालती है। एसिडिटी तब होती है जब पेट में एसिड का उत्पादन सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे गले में जलन महसूस होती है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। सही समय पर सही भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन इस समस्या से निजात पा सकते हैं।



गुनगुना पानी

जिन लोगों को अक्सर गैस, एसिडिटी जैसी बीमारी रहती है, उनके लिए सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना फायदेमंद होता है। इसके सेवन से आंतों को संकुचन में मदद मिलती है। गुनगुना पानी पीना सुबह की एसिडिटी से राहत का सबसे सरल उपाय है। यह पेट में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को शांत करता है। इसके लिए गुनगुने पानी के निरंतर सेवन से आपके शरीर में तापमान की बढ़ोतरी होती है, जिससे शरीर का एंजोक्राइन सिस्टम सक्रिय हो जाता है और पसीना आने लगता है और इसी के कारण शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।

अदरक वाली चाय

अदरक की चाय एसिड रिफ्लक्स सहित कई पाचन समस्याओं के लिए एक प्राचीन प्राकृतिक उपचार है। यह एक लोकप्रिय भारतीय पेय है जो अपने औषधीय लाभों के लिए जाना जाता है। अदरक में सूजन-रोधी और पाचन सुधारने वाले गुण होते हैं, जो एसिडिटी को कम करते हैं। जो एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करते हैं और पाचन संबंधी जलन को शांत करते हैं। अदरक फेनोलिक यौगिकों जैसे रसायनों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह हल्के एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसलिए अदरक वाली चाय पेट में एसिड के उत्पादन को नियंत्रित करती है और पाचन तंत्र को शांत करती है।

सौंफ का पानी

सौंफ का पानी पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। सौंफ में एंटी-अल्सर और एंटी-एसिडिटी गुण होते हैं, जो पेट की जलन को कम करते हैं। खाने के बाद सौंफ खाने से पेट दर्द और अपच आदि की समस्या कम हो सकती है। इसीलिए खाने के बाद सौंफ खाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। सौंफ में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाचन को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा खाने के बाद सौंफ का सेवन करने से सांसों की दुर्गंध भी दूर होती है। सौंफ में मौजूद पाचक रस और एंजाइम पेट फूलना, गैस, अपच और कब्ज को रोकने में बहुत लाभकारी होते हैं।

ठंडा दूध पीएं

ठंडा दूध एसिडिटी को तुरंत कम करने का एक कारगर उपाय है। दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करते हैं, जिससे जलन और खट्टी डकार से राहत मिलती है। सुबह खाली पेट या एसिडिटी होने पर एक गिलास ठंडा दूध धीरे-धीरे पिएं। ध्यान रखें कि दूध कम फैट वाला हो, क्योंकि ज्यादा फैट वाला दूध पाचन को धीमा कर सकता है।



हंसना मना है

टीचर : एक टोकरी में 10 आम हैं, उसमें से 2 आम सड़ गए, बताओ कितने आम बचे? संजू : सर , 10 आम, टीचर : वो कैसे? संजू : सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा ना , केले तो बन नहीं जायेंगे, आज संजू एक वकील है।

गप्पू- क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं, चप्पू- नहीं यार तुम ही बता दो, गप्पू- मुझे पता है मैं बताता हूँ, गप्पू- ताकि, लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें।

हसबैड- डार्लिंग तुम खुबसूरत होती जा रही हो, पत्नी किचन से- तुमने कैसे जाना ? हसबैड- तुम्हें देखकर तो अब रोटियां भी जलने लगी हैं।

एक बाबा औरतों पर ज्ञान दे रहे थे... औरतों के पास यदि अलादीन का चिराग होता तो... जिन्न या तो मेथी छंट रहा होता या फिर मटर छिल रहा होता...

एक हाथी ने रोमांटिक मूड में एक चींटी को छेड़ दिया, चींटी गुस्से में हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शौहर को संभाल लो, वर्ना मर्द हमारे भी छिछोरे हैं और बाहर तुम भी निकलती हो..

कहानी | सच्चा साधु कौन है

एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था, वैसे भी साधु के पास पैसा कहाँ होता था। नाविक सरल था, पढ़ा लिखा तो नहीं, पर समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बात कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते, और कभी अर्थसहित श्रीमद्भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता, और बाबा की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन उस पार उतरने पर साधु नाविक को कुटिया में ले गये, और बोले, वत्स, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया था। अब ये धन मेरे किसी का काम का नहीं, तुम्हारा जीवन संवर जायेगा, तेरे परिवार का भी भला हो जाएगा। नहीं बाबाजी, मैं ये धन नहीं ले सकता, मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा। कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ लालच, और पाप बढ़ायेगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बताया, मुझे तो आजकल लहरों में भी कई बार वो नजर आया। जब मैं उसकी नजर में ही हूँ, तो फिर अविश्वास क्यों करूँ, मैं अपना काम करूँ, और शेष उसी पर छोड़ दूँ। शिक्षा- यह प्रसंग एक सवाल छेड़ गया, इन दोनों पात्रों में साधु कौन था? एक वो था, जिसने दुःख आया, संन्यास लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया, और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, सुपात्र की तलाश करता रहा। और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया, तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई लालच नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया, संन्यास नहीं लिया, पर उस का ईश्वरीय सत्ता में विश्वास जम गया। श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक को ना केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारना है ये सीख गया, और पल भर में धन के मोह को टुकरा गया।

7 अंतर खोजें



जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951



पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

मेघ	नई योजना बनेगी। नए अनुबंध होंगे। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है। परिवार की समस्याओं की चिंता रहेगी। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलेगा।	तुला	यात्रा, नौकरी व निवेश मनुकुल लाभ देंगे। भेंट आदि की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहेगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं। अपनी वस्तुएं संभालकर रखें।
वृषभ	संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। धन की आवक बनी रहेगी। जोखिम व जमानत के कार्य न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी।	वृश्चिक	वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रत्याशित बड़े खर्च सामने आएंगे। कर्ज लेना पड़ सकता है, जोखिम न लें। अजनबी व्यक्ति पर विश्वास न करें। विवादों से दूर रहना चाहिए।
मिथुन	रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। संतान के कार्यों पर नजर रखें। पूंजी निवेश बढ़ेगा।	धनु	कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे। व्यवसाय ठीक चलेगा। तंत्र-मंत्र में रुचि रहेगी। धनार्जन होगा। प्रमाद न करें। संतान के कार्यों से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कर्क	क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दुःखद समाचार मिल सकता है। चिंता बनी रहेगी। व्यापार-व्यवसाय में सावधानी रखें। वास्तविकता को महत्व दें।	मकर	मेहनत का फल मिलेगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शत्रु शांत रहेंगे। धनार्जन होगा। आज विशेष लाभ होने की संभावना है। सगे-संबंधी मिलेंगे।
सिंह	नए अनुबंधों का लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। पूछ-परख रहेगी। रुके कार्य बनेंगे। जोखिम न लें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। खानपान पर नियंत्रण रखें।	कुम्भ	प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी। धनार्जन होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। प्रमाद न करें। भाइयों की मदद मिलेगी।
कन्या	मेहमानों का आवागमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। मान बढ़ेगा। जल्दबाजी न करें। जोखिम के कार्यों से दूर रहें। पराक्रम में वृद्धि होगी।	मीन	वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। दूसरों की जमानत न लें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है।

बॉलीवुड

मन की बात

मुझे रात में बुलाते थे कुछ हीरो इनकार करने पर काम मिलना कम हुआ : मल्लिका शेरावत



मल्लिका ने अपने करियर की शुरुआत से ही बॉल्ड और बिंदस इमेज बना ली थी। उनकी डेब्यू फिल्म ख्वाहिश की कहानी एक रोमांटिक ड्रामा थी, जिसमें प्यार, शादी और रिश्तों के उतार-चढ़ाव को दिखाया गया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण मल्लिका के बेबाक सीन और खुले विचारों वाले किरदार थे। एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि हीरो उन्हें रात में बुलाते थे। कास्टिंग काउच और इंडस्ट्री में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमने कई आंदोलन देखे हैं। हाल ही में टॉप एक्ट्रेस मल्लिका ने इसी मुद्दे पर चौंकाने वाला बयान दिया है। मल्लिका ने अपनी बातचीत में कहा कि कई अभिनेत्रियों को खुलेआम स्वीकार करते देखा है कि कास्टिंग काउच नाम का भूत कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है। कई युवा अभिनेत्रियों ने कई गहरे राज खोले हैं, जैसे कि कैसे कुछ बड़े लड़कों ने ऑफर मिलने पर उनसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की ताकीद की थी। कास्टिंग काउच और इंडस्ट्री में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमने कई आंदोलन देखे हैं। इसी मुद्दे पर मल्लिका ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ हीरो उन्हें रात में आने के लिए मजबूर करते थे। मल्लिका ने भावुक होकर बताया कि समझौता करने से इनकार करने के कारण उन्हें फिल्मों के ऑफर कम मिलते गए। कभी हॉट ब्यूटी के रूप में इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली इस एक्ट्रेस को अब ऑफर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में स्टार हीरोइन के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, वह अपनी बॉल्डनेस के लिए एक पहचान बन गई हैं। बड़ी स्टार हीरोइनों को कड़ी टक्कर देने और कई टॉप हीरो के साथ अभिनय करने के बाद, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई। फिल्मों के साथ-साथ, मल्लिका निजी मामलों को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहीं।

शि

लिया शेड्डी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ते नजर आ रही हैं। कपल पर मुंबई के बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है। शिल्पा शेड्डी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। एक्ट्रेस शिल्पा शेड्डी, उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा और अन्य एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कपल पर मुंबई के ही एक बिजनेसमैन के साथ 60 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जुहू पुलिस स्टेशन में कपल के खिलाफ केस दर्ज कराया चूंकि धोखाधड़ी का मामला 10 करोड़ से ज्यादा का है, पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को केस ट्रांसफर कर



दिया। शिल्पा शेड्डी और राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला 60 साल के दीपक कोठारी ने दर्ज कराया है। दीपक कोठारी, लोटस

कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस के डायरेक्टर हैं। दीपक कोठारी द्वारा दर्ज किए गए केस के अनुसार राजेश आर्या ने शिल्पा और राज कुंद्रा से उनकी मुलाकात कराई थी। राज और

शिल्पा बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे। ये होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म था। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शिल्पा और राज ने 75 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसपर उन्हें 12 प्रतिशत ब्याज देना था। इस ब्याज से बचने के लिए कपल ने हेरफेर कर इसे लोन की बजाए कंपनी में इनवेस्टमेंट के तौर पर दर्शाया। शिकायतकर्ता के अनुसार कपल ने हर महीने ये रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा किया नहीं। एफआईआर के मुताबिक शिल्पा शेड्डी इस लेनदेन की गवाह बनी थीं, लेकिन उन्होंने साल 2016 के सितंबर में कंपनी के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। दीपक कोठारी को बाद में शिल्पा शेड्डी और राज कुंद्रा के पहले के कारनामों की भनक लगी थी।

बॉलीवुड

गपशप

फिर से कमबैक करना चाहती हैं सुष्मिता सेन

मिस यूनिवर्स रह चुकीं सुष्मिता सेन किसी परिचय की मोहताज नहीं। बस हां, इतना जरूर है कि वो पिछले कुछ सालों से पर्दे से गायब नजर आ रही हैं। फैन्स उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सुष्मिता जल्दी सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करें। उनका काम देखने का उन्हें मौका मिले। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुष्मिता ने अपने कमबैक पर बात की है। सुष्मिता ने बताया कि वो कमबैक करना चाहती हैं, क्योंकि घर पर बिना काम के बैठे-बैठे वो बोर हो गई हैं। खुद के लिए वो काम ढूंढ रही हैं। ऐसा नहीं कि सुष्मिता डायरेक्टर्स से बात नहीं कर रही। बल्कि एक्ट्रेस का कहना है कि वो खुद के लिए काफी

प्रोएक्टिव होकर काम ढूंढ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुष्मिता ने बताया कि उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिकों को खुद कॉल की और काम मांगा। साथ ही उनके सामने काम करने की इच्छा जाहिर की। मैंने उन्हें कॉल की और कहा, मैं सुष्मिता सेन बोल रही हूं। मैं एक एक्टर हूं और कमबैक करना चाहती हूं। मुझे आप काम दें। मैंने पिछले 8 सालों से काम नहीं किया है और बहुत लंबा समय हो चला है कि मैं बिना काम किए बैठी हुई हूं। बता दें कि सुष्मिता ने साल 2023 में वेब सीरीज की थी, ताली, जिसमें इन्होंने एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का रोल अदा किया था। सुष्मिता

के लिए इस रोल में ढल पाना बहुत मुश्किल सफर रहा। लोगों को एक्ट्रेस का काम भी पसंद आया, लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी रहे, जिन्होंने वेब सीरीज में कास्टिंग को लेकर सवाल खड़े किए। सुष्मिता ने कहा था कि उन्हें खुद भी इस रोल को अदा करने को लेकर डाउट्स थे, लेकिन फिर खुद गौरी सावंत ने सुष्मिता से इस रोल को करने को लेकर रिक्वेस्ट की, जिसके बाद एक्ट्रेस ने वेब सीरीज की। सुष्मिता को 8 साल हो गए हैं। इन सालों में एक्ट्रेस ने काफी चीजें सीखीं। लाइफ के कई एक्स्पीरियसेस का उन्होंने सामना किया। बतौर आर्टिस्ट उन्होंने काफी ग्रो किया।



अजब-गजब

इस देश में पर्यटकों के लिए बने अजीब नियम!

यहां चप्पल पहनकर किया ड्राइव, तो देना होगा जुर्माना

आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा देस, वैसा भेस। इसका अर्थ होता है कि आप जिस भी देश जा रहे हैं, वहां के लोगों की परंपराओं, मान्यताओं और नियमों का पालन करें और उनके जैसे बन जाएं। इसमें समझदारी भी होती है। मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं कि विदेश जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे टूरिस्ट्स को यूरोप के कई देश सबक सिखाने का ठान चुके हैं। यूरोप के कई देशों ने काफी अजीब नियम बना दिए हैं जैसे कोई महिला बीच के अलावा शहर में बिकिनी पहने नजर आई या फिर कोई शख्स चप्पल पहनकर बाइक या कार चलाते मिला तो उसके जुर्माना देना होगा। अगर आप यूरोप में छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं, तो जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें। लोकप्रिय यूरोपीय पर्यटन शहर अब बढ़ते मास टूरिज्म को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे नियम लागू कर रहे हैं, जिनके उल्लंघन पर हजारों डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। इन नियमों का मकसद है उन पर्यटकों पर लगाम लगाना, जिन्हें स्थानीय प्रशासन अनुशासनहीन मानता है। हैरानी की बात यह है कि कई जुमाने इतने अजीब हैं कि सुनकर हंसी भी आ सकती है, जैसे पिलप-फ्लोप पहनकर ड्राइव करना, बीच से एक शंख या कंकड़ उठाना, या विमान के पूरी तरह रुकने से पहले सीटबेल्ट खोलना। बार्सिलोना, अल्बुफेरा, स्प्लिट, सोरेंटो, कान्स



और वेनिस जैसे शहरों में अगर कोई पर्यटक बीच से बाहर, शहर में स्विमसूट पहने घूमता है, तो उस पर 1,747 डॉलर (करीब 1.45 लाख) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं मालोर्का, इबीज़ा, मागालुफ और कैनरी आइलैंड्स में सड़कों पर शराब पीने पर 3,495 डॉलर (करीब 2.9 लाख) का जुर्माना है। स्पेन में पूल चेंयर पर लंबे समय तक टॉवेल छोड़ने पर भी 291 डॉलर (करीब 24,000) का दंड है। स्पेन, ग्रीस, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल में पिलप-फ्लोप पहनकर ड्राइव करना गैरकानूनी है, और इसके लिए 349 डॉलर (करीब 29,000) का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं ग्रीस में बीच से एक शंख या कंकड़ उठाने पर 1,165 डॉलर (करीब 97,000) का दंड है। अगर आप वेनिस की नहर में तैरते पकड़े गए, तो 407 डॉलर (करीब 34,000) चुकाने होंगे। पर्यटन

कार्यकर्ता बिरगिता स्पी-कोनिंग के अनुसार, स्थानीय लोग तंग आ चुके हैं। ये जुर्माने संकेत हैं कि समुदाय अपनी जगह वापस पाना चाहते हैं। पर्यटक पहले से बुरे नहीं हुए हैं, लेकिन अब सहनशीलता कम हो गए हैं। मलागा (स्पेन) में Improve Your Stay नाम का 10-बिंदु वाला नया अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बसों और होर्डिंग्स पर यह लिखा गया है कि पर्यटक कैसे व्यवहार करें, जैसे कि सभ्य तरीके से कपड़े पहनना, कचरा न फैलाना, जरूरत से ज्यादा शोर न करना, और स्कूटर को लापरवाही से न चलाना। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 873 डॉलर (करीब 73,000) तक का जुर्माना लग सकता है। अल्बुफेरा में सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है कि पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर गलत क्रियाएं, पेशाब करना, खाना बनाना या कैपिंग करना सख्त मना है। अधिकारियों का कहना है कि ये सख्त नियम स्थानीय लोगों और जिम्मेदार पर्यटकों दोनों की सुरक्षा और आराम के लिए हैं। स्पेनिश टूरिज्म ऑफिस, लंदन की प्रेस हेड जेसिका हार्वी टेलर ने कहा, ये नियम सुनने में भले ही कठोर लगें, लेकिन इनका मकसद जिम्मेदार और संवेदनशील यात्रा को बढ़ावा देना है। ये ज्यादातर ऐसे पर्यटकों की छुट्टियों के अनुभव की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो छुट्टी के दौरान जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं।

6 फुटियों का परिवार, सब हैं ताड़ के पेड़ जैसे लंबे, हर साल कमाते हैं 82 करोड़

अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चों की हाइट मां-बाप पर जाती है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने माता-पिता से भी ऊंचे हो जाते हैं। पर अमेरिका का एक परिवार हाइट के मामले में बेहद अनोखा है क्योंकि इस परिवार में सभी लोग 6 फीट से ऊपर हैं। इस वजह से इसे 6 फुटियों का परिवार कहा जाता है। ये लोग हर साल 82 करोड़ रुपये कमाते हैं। इनकी कमाई का तरीका आपको चौंका देगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाला टेमारा परिवार इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे लंबे परिवार के रूप में छाया हुआ है। इस परिवार की ऊंचाई 6 फुट 3 इंच से लेकर 6 फुट 10 इंच तक है और यही उनकी पहचान और कमाई का जरिया बन गया है। परिवार की सबसे चर्चित सदस्य 6 फुट 2 इंच लंबी मारी टेमारा हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 30 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और सालाना लगभग 10 मिलियन डॉलर (करीब 82 करोड़ रुपये) कमाती हैं लेकिन मारी परिवार में सबसे लंबी नहीं हैं। उनके बड़े भाई ट्रॉय की ऊंचाई 6 फुट 10 इंच और शेन की 6 फुट 9 इंच है। दोनों बास्केटबॉल खेल चुके हैं और कमाई में भी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहां ट्रॉय सालाना 1 लाख डॉलर कमा रहे हैं, वहीं शेन 50 हजार डॉलर कमा रहे हैं। मारी की मां क्रिस्टीन (63 वर्ष, 6 फुट 5 इंच) पहले इमरजेंसी ऑपरेटर के रूप में काम करती थीं, लेकिन अब ऑनलाइन पुरुषों के जूते (यूके साइज 13) की तस्वीरें बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। मारी के पिता माइकल (65 वर्ष, 6 फुट 3 इंच), जो पहले इलेक्ट्रिशियन थे, अब परिवार के कंटेन प्रोजेक्ट में शामिल होकर सालाना 50 हजार डॉलर कमा रहे हैं। मारी बताती हैं कि उनका बचपन आर्थिक रूप से कठिन था। माता-पिता ने हमेशा बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता दी, लेकिन खुद के लिए कभी ज्यादा खर्च नहीं किया। यही वजह है कि अब उन्हें अपने परिवार को आर्थिक रूप से सिक्योर देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती है। करीब चार साल पहले मारी ने अपनी 1 लाख डॉलर सालाना की अकाउंटेंट की नौकरी छोड़कर OnlyFans पर काम शुरू किया। शुरुआत में वह अकेले वीडियो बनाती थीं, लेकिन माता-पिता और भाई अक्सर बैकग्राउंड में नजर आ जाते थे या शूट में मदद करते थे। धीरे-धीरे मारी ने उन्हें छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स में शामिल करना शुरू किया। सबने बिना झिझक हामी भर दी, मां को यह मजेदार लगा, पिता को हंसी आई और भाइयों ने इसे चुनौती के रूप में लिया।



दिल्ली के लिए विपदा बनी भाजपा सरकार : भारद्वाज

आप नेता बोले- जलभराव पर नहीं छिपा सकती नाकामी

» एसआई पर भी सवाल कहा- सुधार की जरूरत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश और उससे पैदा हुए जलभराव ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। आए दिन कहीं दीवार गिर रही है, तो कहीं पेड़ या बिजली के खंभे गिरने से हादसे हो रहे हैं। इस बात को लेकर अब राष्ट्रीय राजधानी में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में जलभराव और इससे हो रही मौतों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दिल्लीवालों के लिए विपदा बन चुकी है। वह दूसरों पर दोष मढ़ कर जलभराव रोकने में अपनी नाकामी को नहीं छिपा सकती। बता दें कि शुक्रवार को बारिश में पानी जमा होने से दरगाह शरीफ पट्टे शाह परिसर में छत गिरने से 6 लोगों की मौत बेहद दुखद है।

गुरुवार को भी बारिश के चलते पेड़ गिरने से बाइक सवार और डीडीए की दीवार गिरने के दो बच्चों की दुखद मौत हो गई थी। सौरभ ने कहा कि पिछले तीन महीनों में दिल्ली में बारिश से जुड़ी घटनाओं में लगभग 30 लोगों की जान जा चुकी है। पेड़, दीवारें, खंभे और अब छतें गिर रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार सिर्फ डीसीलिंग के दावे करती रही, लेकिन नतीजा क्या निकला? दिल्ली हर बारिश में पानी-पानी हो रही है। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा

कि क्या कालकाजी में पेड़ गिरने से मरे व्यक्ति की मौत के लिए भी अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं? क्या बिजली कटने, स्कूलों की फीस बढ़ने के लिए भी केजरीवाल जिम्मेदार हैं? उन्होंने कहा कि कई बार लोग अपनी पुरानी इमारतों की मरम्मत भी नहीं करवा पाते क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) के अधिकारी आकर रोक देते हैं या पैसे मांगते हैं। पंचशील, चिराग दिल्ली, शाहपुर जाट जैसे इलाकों में लोग परेशानी झेल रहे हैं। सौरभ ने कहा कि इस कानून में भी सुधार



विधायक जनरैल सिंह ने भी सरकार पर साधा निशाना

उधर तिलक नगर से आप विधायक जनरैल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीडियो में सिंह जलभराव वाली सड़क पर बोटिंग करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने हर वाली-मोहल्ले में राफिंग की सुविधा दे दी है। दिल्लीवासी बोट खरीद लें और हर बारिश में गुप्त राफिंग का मजा लें। टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा।

जरूरी है। इसके साथ ही आप नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा की चार इंजन वाली सरकार को जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। वे सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जैसे केंद्र सरकार हर मुद्दे के लिए नेहरू जी को दोष देती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सिर्फ भाषण देने और दूसरों पर दोष मढ़ने से कुछ नहीं होगा। भाजपा को जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। दिल्लीवासियों ने उन्हें शासन करने के लिए चुना है, जिम्मेदारी से भागने के लिए नहीं।

चुनाव आयोग की बीजेपी से है सांठगांठ : ढांडा

» आप नेता का आरोप- दिल्ली चुनाव में वोट चोरी कर जीती भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रोहतक। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने चुनाव आयोग पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ढांडा ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा राजनीतिक दलों पर फोड़ना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है, जिसके चलते आयोग को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ढांडा ने आगे कहा चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिलीभगत अब सबके सामने आ चुकी है इसलिए आयोग अब राजनीतिक दलों पर दोष मढ़ रहा है। वोटर लिस्ट में पहले भी राजनीतिक दलों ने खामियां निकाली थीं तो चुनाव आयोग कहता था कि ये राजनीतिक दलों का काम है और अब बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग एसआईआर (स्पेशल इंटेसिव रिवीज्ण) कर रहा है।



अनुराग ढांडा ने कहा इससे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत उजागर हुई है। उन्होंने कहा दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी वोट चोरी कर जीती है। उस समय वोटर लिस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी ने काफी आपत्तियां दर्ज की थीं जिन्हें चुनाव आयोग ने सुना तक नहीं था। विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने बीजेपी का पूरा साथ दिया था। ढांडा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आप सरकार के दौरान हम शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। आज वही शिक्षक बीजेपी की रैलियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि अगर आप वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, तो लोग आपकी रैलियों में नहीं आएंगे।

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

» वैष्णव खंड गोमती नगर विस्तार जनकल्याण समिति ने लोगों में भरा देश भक्ति का जोश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। वैष्णव खंड जनकल्याण समिति ने गोमतीनगर विस्तार सेक्टर 6 में 79वें स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सर्वप्रथम झंडारोहण समिति की अध्यक्ष नीलिमा जोशी और प्रधान पंकज सिंह द्वारा किया गया तत्पश्चात कार्यक्रम में गोमती नगर विस्तार के सभी रहवासियों स्कूली बच्चों व समाजसेवियों ने सहभागिता निभाई। समिति के सदस्य प्रमोद जोशी ने जिला और राज्य स्तर पर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। जिसमें अकर्ष सिंह सूर्यवंशी जिन्होंने



97 प्रतिशत अंक आईसीएसई से अर्जित कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। इसी क्रम में अनायिका ने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में मेडल और अथर्व विश्वकर्मा ने स्केटिंग में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ब्रॉज और सिल्वर पदक जीतकर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। ध्वजारोहण के पश्चात स्कूली बच्चों, महिलाओं व पुरुषों और शारदा वेलफेयर सोसाइटी के बच्चों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

कूड़े और टूटी सड़कों को लेकर उग्र प्रदर्शन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी के मड़ियाव इलाके में अव्यवस्थित सफाई और बदहाल सड़कों को लेकर स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम और पार्श्व पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ओवरब्रिज के नीचे जमा कूड़े के ढेर पर चारपाई रखकर धरना दिया और नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए। निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से सड़कें जर्जर पड़ी हैं और जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। इसके अलावा ओवरब्रिज के नीचे लगातार कूड़े का ढेर इकट्ठा किया जाता है, जिससे बदबू और गंदगी से लोग परेशान हैं।

बार-बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इलाके की सफाई और सड़क मरम्मत का कार्य नहीं शुरू किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। लोगों ने कहा कि गंदगी



क्षेत्रीय लोगों की आवाज भी नहीं सुनता नगर निगम

अजीत कुमार मोर्य निवासी फैजुल्लागंज वार्ड क्षेत्र की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ये फैसला किया है कि जो कूड़ा कचरा मड़ियाव ब्रिज के नीचे लगाया जाता है उससे हम सभी नागरिकों को काफी दिक्कत होती है इसकी शिकायत कई बार मीडिया के माध्यम और शिकायत भी की लेकिन लखनऊ नगर निगम और स्थानीय पार्श्व अंगण और लापरवाह बने हैं। मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्थानीय निवासियों की एक ही मांग कूड़े को रोड पर न गिराया जाए।

और खराब सड़कों के चलते आए दिन राहगीरों और बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं, बीमारियों के फैलने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अब की बार वे ढिलाई सहन नहीं करेंगे और

आवश्यकता पड़ने पर बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराएंगे। नगर निगम और स्थानीय पार्श्व पर दबाव बढ़ने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन इस पर सज्जन लेगा और जल्द ही सफाई व मरम्मत कार्य शुरू करेगा।

उद्घाटन मुकाबले में मेरठ ने दिखाया दम

» यूपी टी-20 लीग का तीसरे सीजन का रंगारंग आगाज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से यूपी टी-20 लीग का तीसरा सीजन 17 अगस्त से शुरू हो गया है, जो 6 सितंबर तक चलेगा। वहीं, उद्घाटन मुकाबले में मेरठ मेवरिक्स ने कानपुर सुपरस्टार्स को 86 रन से हराया। माधव कौशिक के आतिशी 95 रन की पारी के चलते मेरठ ने कानपुर को 86 रन से पराजित किया। मेरठ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में कानपुर की टीम 139 रन पर ही ऑल आउट हो गई।

कानपुर सुपरस्टार्स को 86 रन से हराया



कानपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। मेरठ पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 6.2 ओवर में 32 रन की साझेदारी की। इसके बाद में ऋतुराज शर्मा और अक्षय दुबे के बीच में लंबी साझेदारी हुई। इसके बाद में

माधव कौशिक और ऋतुराज शर्मा ने निर्धारित 20 ओवर में टीम का स्कोर 225 रन तक ले गए। जवाब में कानपुर की टीम कुछ खास नहीं कर पाई। कसान समीर रिजवी के 36 रेंड में 45 रन और गौतम ने 20 रेंड में 34 रन के अलावा टीम का कोई भी खिलाड़ी

एशिया कप: कल हो सकता है भारतीय टीम का ऐलान

नई दिल्ली। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल होने को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। एशिया कप का आयोजन नौ से 28 सितंबर तक यूएई में होगा। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिल और यशस्वी को एशिया कप में आराम दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस टूर्नामेंट के लिए मंगलवार को भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीम प्रबंधन टी20 के लिए कोर ग्रुप पर ही गंभीरता जता सकता है जिन्होंने गौतम गंभीर की कोचिंग में पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन किया है। गंभीर के मुख्य कोच रहते भारत ने 15 में से 13 टी20 मुकाबले जीते हैं। रिपोर्ट की मानें तो भारत एक अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज की तलाश में है जो यूएई की धीमी पिचों पर बेहतर खेल सके। इसी को देखते हुए श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा को भारत की टी20 टीम में शामिल किया जा सकता है।

कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सका।



चुनाव आयोग के गले की हड्डी बना हाउस नम्बर जीरो!

विपक्ष के आरोपों की बौछार जवाब की दरकार, कांग्रेस का पलटवार, जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते

» एसआईआर पर भी माथा पच्ची कर रहा है चुनाव आयोग

» सुप्रीम कोर्ट में बिहार में लाखों लोगों के काटे गये नामों का चुनाव आयोग द्वारा जवाब देना अभी बाकी है

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकतंत्र की रीढ़ कही जाने वाले चुनाव आयोग जिसे कभी निष्पक्षता और निर्भीकता की पहचान माना जाता था आज खुद कठघरे में है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर हल्ला बोलने के बाद चुनाव आयोग ने पहली बार प्रेस कांफ्रेंस कर उनके आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देने की कोशिश की।

चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को सात दिनों के भीतर हलफनामा देने की बात कही है वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दे सका। एनसीपी (एसपी) सांसद अमोल कोल्हे ने



संसद में सोमवार को एसआईआर एवं वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करते इंडिया गठबंधन के सदस्य।

मीडिया से बात करते हुए कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई मुद्दों और सवालों को उठाया था जिनके जवाब की सभी को उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देने में पूरी तरह विफल रहा। ये उनकी नैतिक

जिम्मेदारी थी कि जो सवाल उठाए गए हैं, उनका सही तरीके से जवाब दिया जाए ताकि आम नागरिकों की शंकाओं का निपटारा हो। मगर उन्होंने सवाल उठाने वाले से ही शपथ पत्र मांगा है, जो संविधान और लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा शपथ पत्र

कांग्रेस सांसद सुखदेव मगत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसमें डायलॉग था कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यह चुनाव आयोग पर बिल्कुल फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि आयोग को भाजपा के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन आयोग ने उन्हें एफिडेविट देने की बात नहीं की वहीं जब राहुल गांधी जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं ने चोरी पकड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्हें एफिडेविट देने की बात कही जा रही है।

राहुल गांधी ने एड्रेस जीरो का जो मुद्दा उठाया है उस पर चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं कि क्या देश में कोई व्यवस्था बाकी नहीं रह गयी है जो इतने अधिक लोगों के जीरो नम्बर पर नाम दर्ज है।

एड्रेस जीरो पर फंस गयी बात

चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के लिए मकान नम्बर अनिवार्य है। ऐसे में कैसे संभव है कि इतने अधिक नाम जीरो नम्बर पर एनाल कर लिये गये हों। कांग्रेस ने कहा है कि इस पूरी व्यवस्था की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

वोट चोरी बंद करो

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वोट चोरी बंद करो तो हम चोर कहना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि महदेवपुर के एक लाख वोटों का हिसाब किसी ने क्यों नहीं दिया? अनुराग ठाकुर छह विधानसभा क्षेत्रों की डिजिटल मतदाता सूची लेकर घूम रहे हैं उन्हें यह कहाँ से मिली? क्या यह निजता का उल्लंघन नहीं है? क्या चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया? नहीं। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज की बात आती है तो आप कहते हैं कि यह निजता का उल्लंघन है।

बीजेपी के लिए अब अपरिहार्य नेता नहीं रहे प्रधानमंत्री मोदी

» सीपी राधाकृष्णन का नाम हो या फिर कांस्टीट्यूशन क्लब के इलेक्शन पर उठ रहे सवाल

» राजनीतिक तौर पर कमजोर होते पीएम मोदी!

» सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आने के बाद उपराष्ट्रपति कंट्रोवर्सी पर लगा ब्रेक

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति कंट्रोवर्सी से शुरू हुआ बीजेपी के भीतर का पावर गेम सीपी राधाकृष्णन के नाम आने के बाद शांत हो गया है। इस शांति को तूफान के बाद की शांति कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी अब राजनीतिक तौर पर कमजोर हो गये हैं। संघ ने पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली है और सीपी राधाकृष्णन संघ का सुझाया हुआ नाम है जिसे पीएम मोदी और जेपी नड्डा को मानना पड़ा।

पहले राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का नाम हो या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हर बार माना गया कि अंतिम मोहर मोदी-शाह की थी। लेकिन इस बार सीपी राधाकृष्णन का नाम संघ ने आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री मोदी को इसे स्वीकार करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना इस बात का सबूत है कि मोदी अब वह अपरिहार्य नेता नहीं रहे जिसकी मर्जी के बिना पार्टी का पत्ता भी नहीं हिलता।

पिछले दिनों उपराष्ट्रपति पद को लेकर बीजेपी के भीतर भारी खींचतान रही। कई नाम सामने आए जिनमें भाजपा के वरिष्ठ सांसद तमिलनाडु और बिहार से जुड़े नेता तक शामिल थे। एक धड़ा चाहता था कि उम्मीदवार बिहार से हो ताकि वहां की राजनीति में पार्टी की पकड़ मजबूत हो। दूसरा धड़ा तमिलनाडु से



पीएम मोदी की कमजोर होती पकड़

प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यह रही कि वे फैसलों को एकतरफा करने में माहिर थे। लेकिन यह पहली बार है जब यह धारणा टूटी है। मोदी अब संघ की सहमति के बिना बड़े पदों पर नाम आने नहीं बढ़ा सकते। भाजपा में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन की राजनीति मोदी की सर्वमान्य छवि से बड़ी हो गई है। वहीं भाजपा नेताओं में अब यह खुलकर कहा जाने लगा है कि पार्टी की कमान धीरे-धीरे फिर से संघ के पास लौट रही है। संघ के इस फैसले को केवल उपराष्ट्रपति पद तक सीमित नहीं देखा जा सकता। दरअसल इस फैसले को 2029 और उसके बाद के दौर की तैयारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। संघ यह नहीं चाहता कि मोदी के बाद भाजपा नेतृत्व विहीन हो जाए। इसलिए धीरे-धीरे संगठन की पकड़ मजबूत की जा रही है। सीपी राधाकृष्णन जैसे नाम यह संदेश देते हैं कि भाजपा केवल मोदी ब्रांड पर टिकी नहीं है बल्कि उसका असली आधार संघ ही है।

अखिलेश यादव ने पूछा- एक उपराष्ट्रपति थे वे कहां गए?

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाए जाने पर कहा, उपराष्ट्रपति पद खाली है तो बनना ही था। एक उपराष्ट्रपति थे वे कहां हैं? नए बन जाएंगे अच्छी बात है। हम क्या फैसला लेंगे वह अलग बात है।

नाम चाहता था ताकि दक्षिण भारत में पार्टी के लिए नया आधार तैयार किया जा सके। आखिरकार संघ ने अपने पुराने वफादार और अपेक्षाकृत कम विवादित चेहरे सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगा दी। पीएम मोदी और नड्डा को यह फैसला मानना पड़ा। इससे साफ है कि भाजपा के भीतर सत्ता समीकरण बदल रहे हैं।

राहुल को देखने पेड़ों व बसों पर चढ़े लोग

» वोटर अधिकार यात्रा में समर्थकों और पुलिस में हुई धक्का-मुक्की

» औरंगाबाद में सूर्य मंदिर के दर्शन कर गयाजी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन भी राहुल गांधी के साथ हजारों की भीड़ उमड़ी। लोगों में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद का इतना क्रेज देखने को मिला की लोगों ने पुलिस से धक्का-मुक्की तक की। लोगों का उतावलापन इतना बढ़ा हुआ था कि अपने नेता को एक झालक पाने को लोग पेड़ व बसों तक पर चढ़ गए।

नेता प्रतिपक्ष औरंगाबाद में सूर्य मंदिर के दर्शन कर गयाजी भी पहुंचे। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गयाजी पहुंचा काफिला फिलहाल गयाजी के डबूर में रुका है। शाम साढ़े 6 बजे खलिश पार्क चौक में जनसभा होगी।



मुंबई में भारी बारिश से थमी रफ्तार, यूपी में बढ़ी उमस

» पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाओं में कई की गई जान

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। इस समय उत्तर से लेकर पश्चिम तक बारिश को कहर जारी है। जहां पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं, वहीं महाराष्ट्र में मौसम ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। शहरों से लेकर गांवों तक हालत खराब है। मुंबई में तो 72 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। सोमवार की भारी बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी।

उधर हालांकि यूपी में दो-तीन दिन

राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बचाने की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुकी है और इस जंग के नायक बने हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने न केवल प्रदेश के बच्चों की आवाज उठाई, बल्कि हजारों स्कूलों को मर्ज किए जाने के खिलाफ खुद कोर्ट में याचिका दायर कर दी।

उनका कहना है कि यूपी के मासूम बच्चों का भविष्य किसी राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा नहीं बन सकता, और शिक्षा के अधिकार से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मनीष की पीठ ने आप नेता को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी।

आज 18 अगस्त को उनकी याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी.



लाखों परिवारों की आजीविका को करेगी प्रभावित

यूपी सरकार ने करीब 5,000 से अधिक स्कूलों को मर्ज के नाम पर बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे 27,000 परिषदीय विद्यालय प्रभावित होंगे और 1,35,000 सहायक शिक्षक तथा 27,000 प्रधानाध्यापक के पद खत्म हो जाएंगे। शिक्षानिर्गो और रसोइयों की सेवाएं भी खतरे में आ जाएंगी। यह स्थिति केवल शिक्षा तंत्र ही नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका को भी प्रभावित करेगी।

मसीह की पीठ के समक्ष रखा गया है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में अभिभावकों और बच्चों की पीड़ा को रखेंगे। संजय सिंह का यह कदम उन लाखों परिवारों की उम्मीद बना है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनका भविष्य सरकार के इस फैसले से प्रभावित हो सकता है।



बारिश के थमने की खबर है। पर इस बीच उमस बढ़ जाने लोग परेशान हो रहे हैं। आद्रता बढ़ जाने से लोगों गर्मी ने बीमार करना शुरू कर दी। वहीं मुंबई शहर के विले पार्ले के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया। सायन के गांधी मार्केट इलाके में कई फीट पानी भर गया

और गाड़ियां जाम में फंसी हुई। अंधेरी-बोरिवली से लेकर दादर-चर्चगेट तक यही आलम रहा। हालात देखते हुए बीएमसी ने स्कूल-कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। उसने 1916 हेल्पलाइन नागरिकों के लिए जारी की है। बीएमसी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। आईएमडी ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे सहित कोंकण और महाराष्ट्र के घाट इलाकों में भारी से लेकर कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश की संभावना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।